

## झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 656 राँची, सोमवार,

20 भाद्र, 1938 (श॰)

11 सितम्बर, 2017 (ई॰)

## कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

अधिसूचना 7 जुलाई, 2017

संख्या- 1023 नि॰-- झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम, 2005 (2005 का 11) में निहित प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-2519 दिनांक 23 नवम्बर, 2006 एवं असाधारण गज़ट संख्या-647 दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 में सक्षम अधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को परिभाषित करते हुए अधिसूचित किया गया है।

संदर्भित अधिनियम की धारा-10 के अंतर्गत प्रवेश तलाशी और अधिग्रहण शक्ति हेतु(1) सक्षम प्राधिकारी सभी जिलों के अनुमंडल पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी से तात्पर्य झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पदाधिकारी जो झारखण्डपशुचिकित्सापरिषद् से निबंधित हों तथा झारखण्ड सरकार द्वारा किसी अनुमंडल/ जिला/ क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन पदाधिकारी के पद पर आसीन हो होंगे या ऐसे व्यक्ति को जो सक्षम प्राधिकारों या पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा इस निमित लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति हों होंगे।

उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में उन्हें यह शक्ति होगी की वे अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर किसी परिसर में प्रवेश करें तथा उनका निरीक्षण करें एवं उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे । साथ ही प्रवर्तनसम्बंधित कार्रवाई हेतु अधिकृत किया जाता है ।

- (2) अधिनियम की धारा-10 के उपबंध-3 के सफल क्रियान्वयन हेतु सब इंस्पेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस पदाधिकारी होंगे ।
- (3) अधिनियम की धारा-10 उपबंध-3 (ग) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा झारखण्डगो सेवा आयोग के सदस्य, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, झारखण्ड के सदस्य, जिला पशु क्रुरता निवारण समिति के सदस्य, वन विभाग के प्रभागीय वन पदाधिकारियों, ग्रामीण विकास विभाग के प्रखंड विकास पदाधिकारियों, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अंचल अधिकारी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के राजकीय पशु चिकित्सालयों में पदस्थ समस्त तथा अन्य विभागीय पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को उनके विधिक कार्यक्षेत्र की सीमा के अंतर्गत प्रवर्तन सम्बन्धी कार्रवाई करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

इन अधिकारों का प्रयोग जिलों के उपायुक्त के मार्ग निर्देशन में व अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ किया जायेगा । साथ ही सम्बंधित प्रावधानों के सफलतापूर्वक अनुपालन करने में आवश्यकतानुसार अपेक्षित पुलिस बल की उपलब्धता सम्बंधित वरीय आरक्षी अधीक्षक/ आरक्षी अधीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

उक्त अधिकारों का प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल (आई॰ए॰एस॰)

सरकार के सचिव।

\_\_\_\_\_